NEERAJ®

M.P.A. - 15

लोक नीति एवं विश्लेषण

(Public Policy and Analysis)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Ved Prakash Sharma,* **M.A. (Pol. Science)**

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

लोक नीति एवं विश्लेषण

(Public Policy and Analysis)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1
Question Paper—December-2023 (Solved) 1
Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1
Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved) 1
Question Paper—June, 2018 (Solved) 1
Question Paper—December, 2017 (Solved) 1
Question Paper—June, 2017 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

1. लोक नीति को समझना (Understanding Public Policy) 1
2. नीति चक्र (Policy Cycle) 8
3. लोक नीति के मॉडल (Models of Public Policy) 12
4. लोक नीति का महत्त्व : समकालीन संदर्भ 19
(Importance of Public Policy: Contemporary Context)
5. नीति विज्ञान (Policy Sciences) 25
6. नीति-निर्माण में अंत:सरकारी संबंधों की भूमिका 30
(Role of Inter-Governmental Relations in Policy-Making)
7. नीति निरूपण में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका 38
(Role of Planning Commission and National Development Council in Policy-Making)
8. नीति-निर्माण में मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका 44
(Role of Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office in Policy-Making)

9. नीति-निर्माण में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका 52
(Role of Civic Society Organisations in Policy-Making)

10. नीति-निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की भूमिका 60
(Role of International Agencies in Policy-Making)

11. लोक नीति निरूपण में व्यवरोध (Constraints in Public Policy Formulation) 70

12. लोक नीति : कार्यान्वयन प्रणाली और मॉडल 76
(Public Policy: Implementation System and Models)

13. नीति कार्यान्वयन में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका 82
(Role of Various Agencies in Policy Implementation)

14. नीति कार्यान्वयन में समस्याएँ (Problems in Policy Implementation) 88

15. लोक नीति की मॉनीटरिंग–I (Monitoring of Public Policy–I) 94

16. लोक नीति की मॉनीटरिंग–II (Monitoring of Public Policy–II) 100

17. नीति मूल्यांकन को समझना (Understanding Policy Evaluation) 104

18. नीति प्रभाव को निश्चित करना (Ascertaining Policy Impact) 113

19. नीति विश्लेषण (Policy Analysis) 120

20. नीति विश्लेषण : विधियाँ और तकनीकें–I 125
(Policy Analysis: Methods and Techniques–I)

21. नीति विश्लेषण : विधियाँ और तकनीकें–II 129
(Policy Analysis: Methods and Techniques–II)

22. नीति विश्लेषण : इष्टतमीकरण अध्ययन (Policy Analysis : Optimization Studies) 138

23. विनिवेश नीति : भारत का केस अध्ययन (Disinvestment Policy: A Case study of India) 147

24. दूरसंचार नीति : भारत का केस अध्ययन (Telecom Policy : A Case Study of India) 153

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

लोक नीति एवं विश्लेषण

(Public Policy and Analysis)

M.P.A.-15

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में कम-से-कम* **दो** *प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. लोक नीति की प्रकृति और महत्त्व की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'लोक नीति का स्वरूप', पृष्ठ-4, 'लोक नीति का महत्त्व'

प्रश्न 2. तर्कसंगत नीति निर्माण मॉडल की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-14, 'तर्कसंगत नीति निर्माण मॉडल'

प्रश्न 3. नीति विज्ञान के बारे में लासवेल के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-25, 'लॉसवेल के विचार और नीति विज्ञान'

प्रश्न 4. भारत में नागरिक समाज संगठन की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-52, 'भारत में नागरिक समाज संगठन'

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) नीति-निर्माण में कैबिनेट सचिवालय की भूमिका

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-44, 'नीति-निर्माण में मंत्रिमण्डल सचिवालय की भूमिका'

(ख) अंतर-सरकारी संबंधों के मॉडल

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-31, 'अंत:सरकारी संबंधों के मॉडल'

भाग-II

प्रश्न 6. नीति-निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-65, 'नीति-निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की भूमिका : विश्लेषण और सुझाव'

प्रश्न 7. नीति कार्यान्वयन में प्रशासनिक संगठनों की भूमिका और उत्तरदायित्वों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-82, 'परिचय', पृष्ठ-83, प्रशासनिक संगठनों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व', पृष्ठ-85, प्रश्न 1

प्रश्न 8. नीति निगरानी में प्रमुख बाधाओं को उजागर कीजिए और उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-15, पृष्ठ-97, प्रश्न 2

प्रश्न 9. 'समस्त नीति प्रक्रिया में नीति मूल्यांकन तुलनात्मक रूप से एक उपेक्षित क्षेत्र है।' परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-17, पृष्ठ-104, 'नीति मूल्यांकन : स्वरूप और मूल्यांकन', 'मूल्यांकन के मानदण्ड'

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) नीचे से ऊपर व ऊपर से नीचे दृष्टिकोणों का संश्लेषण

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-79, प्रश्न 1

(ख) कम्प्यूटर सिम्यलेशन

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-21, पृष्ठ-133, 'कम्प्यूटर अनुकरण'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

लोक नीति एवं विश्लेषण

(Public Policy and Analysis)

M.P.A.-15

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में कम-से-कम* ***दो*** *प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. लोक नीति के कार्य-क्षेत्र पर चर्चा कीजिए और नीतिगत मुद्दों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-6, प्रश्न 1 तथा प्रश्न 3

प्रश्न 2. नीति विश्लेषण के लिए प्रणाली (सिस्टम) मॉडल का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-12, 'नीति विश्लेषण के लिए प्रणाली मॉडल'

प्रश्न 3. नीति विज्ञान में उभरते संकटों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-27, 'नीति विज्ञान और उभरता हुआ संकट', पृष्ठ-28, प्रश्न 3

प्रश्न 4. नीति निर्माण में अंतर-सरकारी संबंधों की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-34, 'नीति निर्माण में अंत:सरकारी संबंधों की भूमिका : पुनरावलोकन'

प्रश्न 5. नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-45, 'नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका'

भाग-II

प्रश्न 6. 'नागरिक समाज संगठनों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उपचारात्मक उपायों से निपटा जा सकता है।' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-55, 'नागरिक समाज संगठन : चुनौतियाँ'

प्रश्न 7. नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-68, प्रश्न 2

प्रश्न 8. नीति वितरण के विभिन्न मॉडल क्या हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-77, 'कार्यान्वयन दृष्टिकोण/मॉडल'

प्रश्न 9. नीति विश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-19, पृष्ठ-121, 'नीति विश्लेषण की प्रक्रिया'

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए–

(क) प्रभावी नीति निगरानी व्यवस्था

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-15, पृष्ठ-96, 'प्रभावकारी मॉनीटरिंग के लिए उपाय'

(ख) नीति प्रभाव के प्रकार

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-18, पृष्ठ-114, 'प्रभाव के प्रकार अथवा आयाम'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

लोक नीति और विश्लेषण

(Public Policy and Analysis)

लोक नीति को समझना

(Understanding to Public Policy)

1

परिचय

1950 के दशक के प्रारंभ में एक शैक्षिक खोज के रूप में 'लोक नीति' का आविर्भाव हुआ और तबसे यह एक नया आयाम प्राप्त करने के साथ विधा का स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। सरकार के परिणामों का अध्ययन, अब कई सामाजिक विज्ञान की विधाओं, जैसे–राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और प्रबंधन में नीति प्रमुख कारक बन गया है। लोक नीति की प्रगति इतनी तीव्रता के कारण अनेक अनुसंधानकर्त्ता, शिक्षक और लोक प्रशासक अब यह मानने लगे हैं कि यह निरंतर उत्तरोत्तर कठिन बनती जा रही है। स्पष्ट रूप से लोक नीति से संबंधित विधाएं सीमांकन की पुरानी शैक्षिक पक्तियों को नकार रही हैं।

इस अध्याय के अंतर्गत लोक नीति एवं उसका महत्त्व, लोक नीति का स्वरूप, प्रकार और विषय क्षेत्र, नीति, निर्णय, योजना, लक्ष्य, नीति मूल्यांकन और नीति समर्थन एवं नीति आगत, नीति-निर्गत और नीति परिणाम आदि की चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ : लोक और नीति

सदैव हमारे दैनिक जीवन और शैक्षिक साहित्य में लोक नीति में प्रयोग होने वाले शब्द आते हैं, जहां हम ज्यादातर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, श्रम नीति, विदेश नीति आदि का वर्णन करते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे उन क्षेत्रों में कार्य करना होता है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से विभाजित किया गया है। लोक नीति की संकल्पना पूर्व से यह मानती है कि जीवन का प्रभाव क्षेत्र निजी अथवा पूर्णतः व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन उभयनिष्ठ है। काफी समय पहले लोक नीति पर किए गए सर्वेक्षणों पर राजनीति विज्ञान के अनुसंधानकर्त्ताओं और छात्रों का आधिपत्य था। आमतौर पर उन्होंने सरकार की संस्थागत संरचना और दार्शनिक औचित्य की ओर ध्यान केन्द्रित किया है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सत्ता के क्षेत्र में उनकी सफलता के संबंध में कुछ सीमा तक अनेक राजनीतिक संस्थाओं और समूहों के कार्यकलापों पर विचार किया गया। नीति मूल्यांकन के प्रमुख विद्वान थॉमस डाई ने प्रेक्षण किया कि पारंपरिक राजनीति विज्ञान उन संस्थाओं का उल्लेख करता है, जिनमें लोक नीति सूत्रबद्ध की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रमुख संस्थागत व्यवस्थाओं और लोक नीति की विषयवस्तु के मध्य संबद्धता ज्यादातर अछूती रह गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि आज राजनीति विज्ञान का केन्द्र लोक नीति में हस्तांतरित हो रहा है। लोक प्रशासन के अध्ययन में अब तक निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए यांत्रिक प्रवृत्ति रही है। इसने सरकारी प्राधिकारियों के संगठन, सरकारी कर्मियों के व्यवहार और बढ़ते हुए संसाधन आबंटित करने की विधियों, प्रशासन और विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित किया है। लोक नीति पर किए गए विगत अध्ययनों पर प्रमुखतः राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्वानों का आधिपत्य था और उनमें नीति की विषयवस्तु तथा उसके प्रतिपादन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति थी। लोक नीति के अध्ययन से सामाजिक विज्ञान की नई शाखा सामने आई है और यह नीति विज्ञान कहलाता है।

1. सार्वजनिकता का विचार–सर्वप्रथम लोक नीति की चर्चा हेतु 'सार्वजनिक' संकल्पना को जानना आवश्यक है। हम सामान्यतः 'सार्वजनिक हित', 'सार्वजनिक क्षेत्र', 'लोकमत', 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में लोक नीति को उन क्षेत्रों में कार्य करना है, जिन्हें 'निजी' रूप में शामिल करने वाले की तुलना में 'सार्वजनिक' के रूप में विभाजित

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

किया गया है। आमतौर पर 'सार्वजनिक' विस्तार को 'सार्वजनिक प्रयोजन' के लिए 'सार्वजनिक स्वामित्व' अथवा नियंत्रण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में यह मानवीय कार्यकलाप वह क्षेत्र होता है, जिसके लिए इसमें सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है। डब्ल्यू.बी. वेबर तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर होते हैं–

- यह बाजार की विफलता की क्षतिपूर्ति से ज्यादा चिंतित रहता है।
- इसे सार्वजनिक समर्थन के अल्पमत स्तर को बनाए रखना चाहिए।
- यह ज्यादा कठिन और अस्पष्ट कार्यों को सुलभ बनाता है।
- यह अवसर प्राप्त करने अथवा क्षमताएँ सुधारने से ज्यादा चिंतित रहता है।
- इसके पास निष्पक्षता के पहलुओं की अनुक्रिया करने के ज्यादा अवसर होते हैं।
- यह लोक हित में कार्य करता है।

लोक प्रशासन का आविर्भाव 'निजी' हितों के स्थान पर 'लोक हित' अर्जित करने के लिए राज्य के साधन के रूप में हुआ। मैक्स वेबर के अनुसार, "औद्योगिक समाज में तर्कणापरक प्रक्रिया के कारण अधिकारीतंत्र की वृद्धि हुई थी।" हर्बर्ट सिमॉन के अनुसार नौकरशाहियाँ 'प्रतिबंधित तर्कसंगति' के व्यापक उपाय दर्शाती हैं। म्यूलेर के अनुसार नौकरशाह सदैव लोक हित में कार्य नहीं करते हैं और अपने अलग लक्ष्य रखने की इच्छा रखते हैं। इस संबंध में अधिकारीतंत्र के तुलनात्मक अध्ययन पर अपने कार्य में एबरबैक ने कहा है कि 'इस शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में राजनीतिज्ञ और अधिकारीतंत्र की भूमिकाओं के मध्य वेबेरियन अंतर का आभासी लोप देखा गया है। इससे वह पैदा हुआ, जिसे विशुद्ध संकर रूप में विभाजित किया जा सकता है।'

2. नीति की अवधारणा–'सार्वजनिकता' के विचार की तरह 'नीति' की भी सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। नीति अन्य कारकों के अतिरिक्त कार्यवाही का मार्गदर्शन दर्शाती है। यह निम्नलिखित रूप धारण कर सकती है–

- कार्यविधि की घोषणा
- प्राधिकारिक निर्णय
- लक्ष्यों की घोषणा
- सामान्य प्रयोजन

हॉगवुड और गन्न ने 'नीति' शब्द के कुछ प्रयोग दिये हैं, जैसे–निश्चित प्रस्ताव, वांछित परिस्थितियों की अभिव्यक्ति, कार्यकलाप के क्षेत्र के लिए नाम के रूप में नीति, सरकार के निर्णय, औपचारिक प्राधिकार देना, कार्यक्रम, निर्गम, परिणाम, सिद्धांत अथवा मॉडल एवं प्रक्रिया। राजनीतिक प्रणाली के 'निर्गमों' के रूप में नीति नाम रखने पर जोर दिया जाता है और अनेक कार्यों के संचालन के लिए कमोबेश अन्योन्याश्रित नीतियों के रूप में लोक नीति को परिभाषित करने पर कम जोर दिया जाता है। लेकिन, लोक नीति के अध्ययनों में विनिर्दिष्ट मूल्यों-राजनीतिक मूल्यांकन के बदले व्यक्तिपरक आधार पर नीति-निर्माणों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। वाई. ड्रोर ने नीति की परिभाषा अनुसरण किए जाने वाली कार्यवाहियों के प्रमुख विषय पर सामान्य निर्देशों के रूप में की है। पीटर सेल्फ ने नीतियों को बदलते हुए ऐसे निर्देशों के रूप में बताया है, कि कार्यों को कैसे प्रस्तुत और निष्पादित किया जाना चाहिए। कार्ल फ्रेडरिक नीति को '... बाधाएँ और अवसर पैदा करने वाले निर्धारित वातावरण में व्यक्ति, समूह अथवा सरकार की प्रस्तावित कार्यविधि मानता है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास में प्रयोग करने और हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया था।'

समग्र रूप में देखें तो नीति की परिभाषा कुछ लक्ष्यों के अनुसरण में सत्तासीन व्यक्तियों द्वारा की गई सप्रयोजन कार्यविधि के रूप में की जा सकती है। यहां यह भी शामिल किया गया है कि लोक नीतियां सरकारी निकायों और सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनाई जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।

लोक नीति का स्वरूप

विभिन्न प्रकार की नीतियों से अलग लोक नीति की विशेषताओं का इस तथ्य से पता चलता है कि प्राधिकारी इन्हें किसी राजनीतिक प्रणाली में सूत्रबद्ध करने का काम करते हैं।

लोक नीति के स्वरूप को निम्नलिखित तथ्य और अधिक स्पष्ट करेंगे–

(i) उद्देश्यपरक या परिणामोन्मुखी कार्रवाई लोक नीति का प्रमाण है।

(ii) लोक नीति सरकार के सामूहिक कार्यों का परिणाम है।

(iii) लोक नीति वह है, जो सरकार वास्तव में करती है और जो कुछ बाद में घटित होता है।

(iv) लोक नीति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक रूप में इसमें किसी प्रश्न या समस्या के संबंध में किसी प्रकार की सरकारी कार्रवाई शामिल हो सकती है और नकारात्मक रूप में जहाँ सरकारी मत, अभिवृत्ति या कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, वहाँ कोई कार्रवाई न करने वाले सरकारी अधिकारियों का निर्णय शामिल हो सकता है।

नीति-निर्माण और निर्णयन

नीति के अर्थ को समझने के लिए नीति एवं निर्णय के अन्तर को समझना आवश्यक हो जाता है। सामान्यत: नीति को

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

निर्णय का पर्याय माना जाता है, जो सर्वथा गलत है। नीति के निर्माण में निर्णय प्रक्रिया बार-बार आती है। इस प्रकार निर्णय नीति-निर्माण का एक चरण है। सरकार या कोई संस्था नीति-निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार बार-बार निर्णय लेती है।

सामान्यत: निर्णय का अर्थ है किसी निष्कर्ष पर पहुँचना। **हरबर्ट साइमन** ने कहा भी है कि "*निर्णय विभिन्न विकल्पों में से एक का चयन करना है।*" नीतियाँ अपेक्षाकृत विस्तृत एवं व्यापक होती हैं। ये बहुत-सी समस्याओं को प्रभावित करती हैं, इनका प्रयोग बार-बार किया जाता है। इसके विपरीत, निर्णय किसी विशेष समस्या पर लागू होता है। इस प्रकार निर्णय नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में एक क्षण होता है, फिर भी नीति स्वयं भी किसी निर्णय का ही परिणाम होती है।

निर्णय दो प्रकार के होते हैं–कार्यक्रमबद्ध निर्णय (Programmed Decision) और गैर-कार्यक्रमबद्ध निर्णय (Unprogrammed Decision)। कार्यक्रमबद्ध निर्णय का स्वरूप आवृत्ति एवं नित्यक्रम होता है। इनके लिए निश्चित प्रणालियाँ तैयार की जा सकती हैं तथा प्रत्येक निर्णय पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर गैर-कार्यक्रमबद्ध निर्णय नए होते हैं तथा इनका कोई निश्चित ढाँचा नहीं होता। इन निर्णयों के लिए कोई तैयार पद्धति उपलब्ध नहीं होती है। प्रत्येक विषय पर अलग से विचार करना पड़ता है। आपातकालीन और बिल्कुल नई परिस्थितियों में इस निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है।

नीतियाँ और लक्ष्य

लोक नीति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नीति और उद्देश्य के बीच के भेद को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। सामान्यत: यह मान्यता है कि उद्देश्य नीतियों के लक्ष्य होते हैं। लेकिन यहाँ यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि नीतियाँ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति से ही संबंधित होती हैं। नीति बनने के लिए उद्देश्य का क्रिया के रूप में परिवर्तित होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, गरीबी हटाने की नीति एवं उससे संबंधित योजनाओं की चर्चा की जा सकती है।

नीति-निर्माण और योजना

नीति की रूपरेखा का निर्धारण, नीति-निर्धारकों से दक्षता एवं सामर्थ्य की अपेक्षा रखता है। नीति-निर्धारकों में पर्याप्त सूचनाएँ एकत्र करने एवं उनका विश्लेषण करने, विकल्पों को तैयार करने तथा विकल्पों में से सही का चयन करने की आवश्यक निपुणता होनी चाहिए। नीति-निर्धारकों की दक्षतापूर्ण स्थिति ही उपलब्ध विकल्पों की सीमा का निर्धारण करती है। वास्तविक चुनाव एक प्रकार का राजनैतिक निर्णय होता है, जो यह देखता है कि चुनाव उद्देश्य तथा स्रोत कहां है। नीति का निष्पादन, नीति-निर्माता की प्रेरणा से प्रभावित होता है। नीति-प्रकिया में संबद्ध कार्मिकों द्वारा ली गई रुचि तथा नीतिगत लक्ष्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, नीति के निष्पादन में अभिव्यक्त होती है। किसी नीति का चुनाव करते समय नीति-निर्माता अपनी विचारधारा, जाति तथा वर्गीय हितों या प्रतिबद्धताओं से भी प्रभावित होता है।

कभी-कभी कोई नीतिगत रूपरेखा राष्ट्रीय नीति-निर्माताओं द्वारा न होकर बाहरी स्रोतों से भी सामने आती है और उसे देश की परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जाता है, ताकि उसकी उपयोगिता अक्षुण्ण रह सके। उदाहरण के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उत्पत्ति देश के बाहर हुई थी। इस तरह नीति की रूपरेखा, आंतरिक तथा बाहरी, दोनों तरह के स्रोतों से निकल सकती है।

नीति विश्लेषण और नीति समर्थन

किसी नीति का मूल्यांकन करने का एक अन्य तरीका, उसके क्रियान्वयन में लगे समय तथा लागत के संदर्भ में उसकी कार्यकुशलता का निश्चय करने का है। यह देखा जाना चाहिए कि लागू की गई नीति के तहत, उसके लिए उपलब्ध तथा स्वीकृत धन का इस्तेमाल अत्यन्त उचित ढंग से किया गया है, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। यह भी आवश्यक है कि नीति का क्रियान्वयन निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। समय और लागत आपस में जुड़े हुए कारक हैं, जो कि नीतियों को बनाते अथवा परिवर्द्धित करते हैं। यदि नीति के क्रियान्वयन में हद से ज्यादा समय लिया जाता है, तो नीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक स्रोतों व अन्य अवयवों की लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती है, अत: समय तथा लागत का सीमा से बाहर निकलना रोका जाना चाहिए।

नीति के गुणात्मक मूल्यांकन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह निश्चित करना चाहिए कि नीति जनता के बड़े हिस्से के लिए लाभप्रद हो, दीर्घ अवधि तक टिकाऊ हो तथा जनता की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो। किसी नीति के घोषित उद्देश्य विकासोन्मुख हो सकते हैं, किन्तु कभी-कभी ये आम जनता की माँगों के विरुद्ध भी होते हैं; जैसे–नर्मदा बाँध परियोजना तथा टिहरी बाँध परियोजना।

इस तरह, नीति का मूल्यांकन करने के अनेक आधार हैं। एक नीति को समुदाय के तमाम वर्गों के हितों को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। नीति तभी प्रभावी हो सकती है, यदि उससे जुड़े मुद्दे पर आम सहमति एवं समझौता हो।

नीति विश्लेषण और नीति प्रबंधन

किसी भी देश में प्रभावी नीतिगत मूल्यांकन प्रणाली का होना नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नीति का विधिवत परिवीक्षण एक सुस्पष्ट नीति मूल्यांकन प्रणाली की पहली शर्त है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात यह देखना होता है कि

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

– क्रियान्वयन का तंत्र समुचित ढंग से कार्य कर रहा है;
– क्रियान्वयन में शामिल की गई संस्थाएँ, लोग तथा संस्थान भ्रष्ट तो नहीं हैं;
– कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक स्रोत सुगमता से उपलब्ध हैं तथा उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया गया है;
– आवधिक लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं।

लोक नीति : विषय क्षेत्र

लोक नीति के अध्ययन का एक प्रमुख भाग परिदृश्यों और लोक क्षेत्र में समकालीन प्रवृत्तियों के विकास में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। वर्तमान में जनता की बढ़ती हुई जरूरतों और मांगों के जवाब में विकासशील देशों में विशेषता: जैसे–तकनीकी की समस्या, सामाजिक संगठन, औद्योगीकरण और शहरीकरण अन्य प्रवृत्तियों के प्रभाव में वृद्धि, विकासशील देशों में सरकारों में काफी वृद्धि हुई है। अब वे राष्ट्र निर्माण और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के और ज्यादा कठिन कार्यों से संबंधित हैं। वर्तमान में सरकार केवल शांति की रक्षक है, विवादों के मध्यस्थ और दैनिक सेवाओं की प्रदाता नहीं है। विकासशील देशों में आर्थिम उद्यम और विकास में तीव्रता लाने के लिए वहां की सरकारों पर अत्यधिक दबाव बना रहता है। आज लोक नीतियां रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कराधान, मुद्रास्फीति, विज्ञान और तकनीकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ गहनता से जुड़ी है।

नीतियों के प्रारूप

कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों और विद्वानों ने नीतिगत मुद्दों की चर्चा को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इन मुद्दों और नीतियों के मध्य एक वर्गीकरण का सुझाव इस प्रकार है–1. वितरण, 2. नियंत्रण, 3. पुनर्वितरण और 4. घटक।

पुनर्वितरण संबंधी नीति विषय–पुनर्वितरण नीतियाँ मूलभूत सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने वाली नीतियों से संबंधित हैं। अनेक सार्वजनिक वस्तुओं और लोकहितकारी सेवाओं का वितरण, समाज के कई समूहों में असमान तरीके से होता है, ये वस्तुएं और सेवाएं पुनर्वितरण नीतियों द्वारा सरल और उपयोगी बनाई जाती हैं।

नियमन संबंधी नीति विषय–नियामक नीति विषयों का संबंध कार्यकलाप के विनियमन और नियंत्रण से है। इस प्रकार का विनियमन ऐसे स्वतंत्र संगठन द्वारा किया जाता है, जो सरकार की ओर से कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक, टेलिकॉम नियामक प्राधिकरण, औषधि और मादक पदार्थ नियंत्रक, भारत का महापंजीयक, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड आदि अपने कार्यों में संलग्न हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा आयोग और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे संगठन संवर्धनात्मक और नियामक दोनों प्रकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय विधि परिषद, भारतीय औषधि परिषद एवं भारतीय नर्सिंग परिषद आदि मानकों की सुरक्षा करने के लिए नियामक अभिकरण हैं।

संघटक संबंधी नीति विषय–संघटक नीति विषयों का संबंध संस्थाओं के पुनर्गठन से है। इन नीति विषयों में से प्रत्येक अलग शक्ति क्षेत्र बनाते हैं।

संघर्ष संबंधी नीति विषय–कोबे और एल्डर ने संतुष्टि की जगह संघर्ष के माध्यम से नीति विषयों का वैकल्पिक विभाजन किया है। उनका केन्द्र बिन्दु वह है, जिसमें संघर्ष पैदा किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है, उनके लिए मान-सम्मान और संसाधनों के वितरण से संबंधित पहलुओं पर दो या ज्यादा वर्गों के मध्य संघर्ष पैदा हो सकता है। इन्हें प्रतियोगी पक्ष द्वारा वैकल्पिक नीति के संचालन के रूप में ऐसे उपायों द्वारा पैदा किया जा सकता है, जो संसाधनों के वितरण में पक्षपात महसूस करते हैं।

समझौता संबंधी नीति विषय–हॉगवुड और विल्सन अनेक नतीजों की संभावनाओं की दृष्टि से लागत और लाभ का मानदण्ड प्रयोग करते हैं, जो समझौता और विरोध निर्माण करता है एवं अनेक विकल्प प्रस्तुत करता है। विल्सन के लिए लागत और लाभ का मानदण्ड संकेन्द्रित हो सकता है।

नीति आगत, नीति-निर्गत और नीति परिणाम

नीति आगत कुछ ज्ञात समस्याओं के संबंध में सक्रियता और निष्क्रियता के लिए व्यक्तियों अथवा वर्गों द्वारा राजनीतिक प्रणालियों पर की गई मांग है। राजनीतिक प्रणाली मॉडल में निर्गमों को या तो पर्यावरण पर प्रभावों के रूप में अथवा प्रणाली के राजनीतिक समर्थकों के लिए 'प्रति निवेश' के रूप में जाना जाता है। ईस्टन (1957) के अनुसार निकाय गठित करने अथवा इसका समर्थन करने को राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों के लिए विशेष अभिप्रेरणा निवेश है, जिसे या तो प्रतिबंधों की धमकियों द्वारा अथवा दिए गए समर्थन के लिए लाभ अथवा समाज के राजनीतिक मानदण्डों में समाजीकरण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार नीति आगत कार्यान्वयनकर्त्ताओं के वास्तविक निर्णय हैं।

नीति आगत नीति नतीजों से अलग है। आगत की संकल्पना इस बात पर जोर देती है कि नीति द्वारा प्रभावित होने वाले अभिप्रेत लक्ष्य वर्गों के लिए वास्तव में क्या होता है? इस संबंध में भारत में श्रम कल्याण नीतियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

लोक नीति का महत्त्व

लोक नीति में जनता और उसकी समस्याएँ केंद्र में होती हैं। इसका संबंध पहलुओं और समस्याओं को परिभाषित और संरक्षित करने तथा उन्हें राजनीति और राजनीतिक कार्यसूची में रखे जाने से

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com